RNI No#MPBIL/2013/49052

INVESTMENT AVENUES®
इन्वेस्टमेंट ऐवेन्यूस

भोपाल, शनिवार, 14-20 अक्टूबर 2023 | भोपाल, मध्यप्रदेश से प्रकाशित | वर्ष-12 | अंक- 03 | पृष्ठ-8 | मूल्य- रु. 5/-

इनकम टैक्स रिफंड : अटके 35 लाख मामले

जानिए क्या है वजह और कैसे आएगा पैसा

भोपाल। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास 35 लाख से अधिक रिफंड के मामले अटके हुए हैं। रिफंड जारी करने में यह देरी करदाताओं के बैंक खातों के मिलान और सत्यापन में आ रही दिक्कतों के कारण है। कर अधिकारी ऐसे टैक्सपेयर्स से संपर्क करने के लिए एक स्पेशल कॉल सेंटर स्थापित कर रहे हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के अध्यक्ष नितिन गुप्ता ने मंगलवार को यह जानकारी दी। उनका कहना था, कि विभाग करदाताओं के सही बैंक खातों में जल्दी से रिफंड जमा करना चाहता है।

दिखाई दे रहे पुराने डिमांड नोटिस

उन्होंने कहा कि विभाग ने 2011 के आसपास एक तकनीकी बदलाव किया था और उस समय से पहले के कुछ पुराने डिमांड नोटिस अब करदाताओं के खातों में दिखाई दे रहे हैं। इन पुराने डिमांड नोटिस के कारण रिफंड मामलों में देरी हो रही है।

ऐसे मामलों के लिए विभाग ने बनाया सिस्टम

गुप्ता ने बताया कि विभाग ने ऐसे सभी मामलों के लिए एक यूनिक डिमांड मैनेजमेंट फेसिलिटेशन सिस्टम शुरू किया था। इस सिस्टम के तहत करदाताओं को एक ईमेल भेजा जाता है। इसमें कहा जाता है कि उन्हें तीन दिन में एक दिये गए नंबर से फोन आएगा। इस फोन कॉल के दौरान करदाताओं के मुद्दों को हल करने का प्रयास किया जाता है।

1 साल में 1.4 लाख मामले सुलझाए

उन्होंने कहा कि पिछले एक साल में मैसूर स्थित इस कॉल सेंटर ने 1.4 लाख मामलों को हल किया है। इन मामलों में, करदाताओं को डिमांड नोटिस को स्वीकार करने या उसे चुनौती देने का विकल्प दिया जाता है।

त्योहारों से पहले ग्राहकों को मिला बड़ा तोहफा

अब Fixed Deposit पर ज्यादा लाभ

भोपाल। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ महाराष्ट्र के लाखों ग्राहकों को खुशखबरी दी है। सरकारी बैंक ने अपनी फिक्स्ड डिपॉजिट (Fixed Deposit) पर ब्याज दरों में 1 ।25त्न तक की बढ़ोतरी की है। बीओएम (BoM) ने कहा कि नई दरें 12 अक्टूबर से प्रभावी होंगी। बैंक ने कहा कि ब्याज दरों में बढ़ोतरी एफडी (FD) और बैंक की स्पेशल स्कीम्स पर लागू होगी। बैंक ने कहा कि 46 से 90 दिन की जमा पर ब्याज दर में 1.25 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। इससे व्यक्ति और कारोबार क्षेत्र अधिक बचत को उत्साहित होंगे। एक साल की जमा पर बैंक 6.50 प्रतिशत का ब्याज देगा। एक साल से अधिक की जमा के लिए ब्याज दर 0 ।25त्न बढ़ाकर 6.25 प्रतिशत की गई है। बैंक ने बयान में कहा कि वरिष्ठ नागरिकों को एफडी पर 0.5 प्रतिशत का अतिरिक्त ब्याज मिलेगा। उन्हें 200 से 400 दिन की विशेष जमा योजना पर 7 प्रतिशत की आकर्षक ब्याज दर दी जाएगी। इसमें कहा गया है कि बैंक की आकर्षक ब्याज दरें इसे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म बचतकर्ताओं दोनों के लिए एक आकर्षक विकल्प बनाती हैं, जिससे उनके बीच विश्वास और वफादारी बढ़ती है।

Bank of Baroda के ग्राहकों के लिए RBI ने लिया बड़ा एक्शन, जानिए डीटेल

आरबीआई (RBI) ने बैंक ऑफ बड़ौदा की 'BoB World' मोबाइल ऐप पर नए ग्राहक जोड़ने पर रोक लगाई है। इस आदेश के बाद 'Bob World' ऐप पर नए ग्राहक नहीं जुड़ सकेंगे।

भोपाल। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंक ऑफ बड़ौदा (Bank of Baroda) पर बड़ी कार्रवाई की है। आरबीआई (RBI) ने बैंक ऑफ बड़ौदा की 'BoB World' मोबाइल ऐप पर नए ग्राहक जोड़ने पर रोक लगाई है। BoB को तत्काल प्रभाव से नए ग्राहक जोड़ने पर रोक लगाई गई है। इस आदेश के बाद 'Bob World' ऐप पर नए ग्राहक नहीं जुड़ सकेंगे।

आरबीआई ने जताई चिंता

RBI ने ट्वीट में कहा, बैंक ऑफ बड़ौदा के खिलाफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के सेक्शन 35, 1949 के तहत

बैंक को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दियागया है कि पहले से ही जुड़े 'बॉब वर्ल्ड' (Bob World) ग्राहकों को इस निलंबन के कारण किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़े।

एक्शन लिया गया है। RBI ने बैंक ऑफ बड़ौदा को 'बॉब वर्ल्ड' मोबाइल एप्लिकेशन पर अपने ग्राहकों की आगे की एंट्री को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का निर्देश दिया। यह कार्रवाई इस मोबाइल एप्लिकेशन पर अपने ग्राहकों को शामिल करने के तरीके में देखी गई कुछ सामाग्री चिंताओं पर आधारित है। 'बॉब वर्ल्ड' एप्लिकेशन पर बैंक के ग्राहकों की आगे की भागीदारी आरबीआई की संतुष्टि के अनुसार देखी गई कमियों के सुधार और बैंक द्वारा संबंधित प्रक्रियाओं को मजबूत करने के अधीन होगी। बैंक को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दियागया है कि पहले से ही जुड़े 'बॉब वर्ल्ड' (Bob World) ग्राहकों को इस निलंबन के कारण किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़े।

Vision Invest Tech Pvt. ltd.
+91 7389912003
+91 7389912004

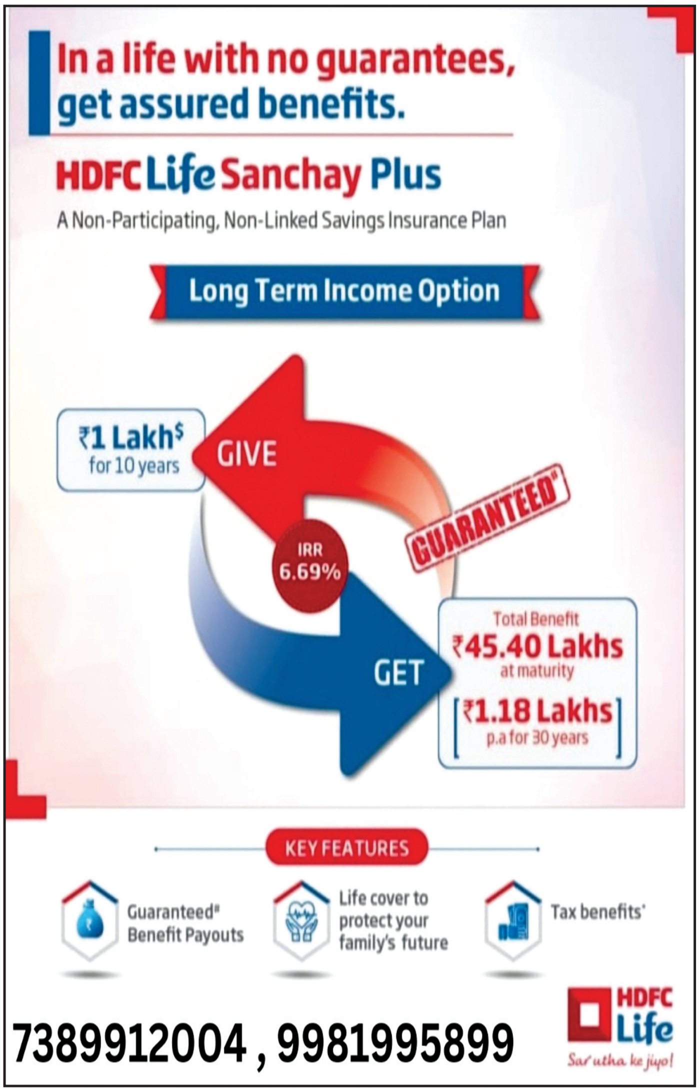

एसआईपी में निवेश पर मिलता है कंपाउंडिंग का लाभ

आ हर महीने 1000 रुपये की एसआईपी करते हैं, तो फिर 30 साल की अवधि में आपके द्वारा जमा की गई रकम महज 3,60,000 रुपये होती है. अब इसमें अगर आपको 20 फीसदी की दर से रिटर्न मिलता है, तो फिर अपका फंड 2,33,60,000 रुपये हो जाता है. कंपाउंडिग का फायदा मिलने से निवेशकों को अच्छा खासा लाभ होता है. कम उम्र में निवेश शुरू करके उसे लॉन्ग टर्म के लिए चालू रखने पर करोड़पति बनने का लक्ष्य पाया जा सकता है।

भोपाल। शेयर बाजार (Share Market) में भले ही भारी उठा-पटक देखने को मिली हो, लेकिन म्यूचुअल फंड को लेकर निवेशकों का सेंटिमेंट सकारात्मक रहा. देश में एक ओर जहां MF Investors की संख्या 4 करोड़ के पार पहुंच गई है, तो वहीं सितंबर महीने में सिस्टामैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी SIP के जरिए रिकॉर्ड निवेश आया है. एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया (AMFI) द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक, बीते महीने एसआईपी में निवेश 16,000 करोड़ रुपये के लेवल से पार निकल गया.

पहली बार निवेश 16000 करोड़ के पार

हर कोई अपनी कमाई में से कुछ न कुछ बचाता है और उसे भविष्य के लिए इन्वेस्ट करता है. इस लिहाज से फिलहाल, SIP इन्वेस्टमेंट के लिए निवेशकों की पहली पसंद बना हुआ है. यही कारण है कि हर बीतते महीने के साथ इसमें निवेश का आंकड़ा बढ़ता ही जा रही है. अगस्त 2023 में SIP में 15,814 करोड़ रुपये लगाए गए थे, तो वहीं सितंबर 2023 में ये आंकड़ा बढ़कर 16,420 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया है. ये अपने आप में रिकॉर्ड है कि पहली बार एसआईपी इन्वेस्टमेंट इस स्तर के पार निकला है.

SIP एयूएम में भी आया उछाल

चालू वित्त वर्ष के पहले छह महीने में SIP के जरिये म्यूचुअल फंड स्कीम्स में 90,304 करोड़ का निवेश हो चुका है. AMFI के आंकड़ों पर नजर डालें तो सितंबर में SIP AUM (एसेट अंडर मैनेजमेंट) भी बढ़कर 8.70 लाख करोड़ हो गया है, जो कि अगस्त महीने में 8.47 लाख करोड़ रुपये था. एसआईपी में मंथली आधार पर एसआईपी इनफ्लो में लगभग 4 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. दूसरी ओर सितंबर महीने में इक्विटी फंडों में 14000 करोड़ रुपये के करीब निवेश हुआ. आज के समय में निवेश के काफी सारे विकल्प हैं, लेकिन इनमें म्यूचुअल फंड खासा पॉपुलर है. इसमें कोई भी निवेशक एसआईपी के जरिए निवेश कर सकता है. SIP की खास बात ये है कि एसआईपी में निवेश लंबी अवधि में काफी प्रभावी होता है और आपको करोड़पति भी बना सकता है. इसमें महज 1000 रुपये महीने की छोटी बचत करते हुए आप दो करोड़ रुपये से ज्यादा का फंड इकठ्ठा कर सकते हैं. इसका एक खास फॉर्मूला भी है.

एसआईपी में कंपाउंडिंग का लाभ

एसआईपी में लॉन्ग टर्म निवेश (Long term Investmet) का सबसे अच्छा फायदा ये होता है कि आपके द्वारा इन्वेस्ट की गई रकम पर आपको कंपाउंडिंग (Compounding) का भी लाभ मिलता है. ऐसे में SIP में मिलने वाला रिटर्न शानदार हो जाता है. एक्सपर्ट्स भी निवेश का प्लान बना रहे लोगों को जितना जल्दी या कम उम्र में हो सके इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने की सलाह देते हैं. यहां पर आप नियमित तरीके से छोटा निवेश करते हुए एक बड़ा फंड बना सकते हैं.

1000 रुपये जमाकर कैसे बनेंगे करोड़पति?

SIP Calculater के जरिए समझें तो आप हर महीने 1000 रुपये की एसआईपी करते हैं, तो फिर 30 साल की अवधि में आपके द्वारा जमा की गई रकम महज 3,60,000 रुपये होती है. अब इसमें अगर आपको 20 फीसदी की दर से रिटर्न मिलता है, तो फिर अपका फंड 2,33,60,000 रुपये हो जाता है. कंपाउंडिग का फायदा मिलने से निवेशकों को अच्छा खासा लाभ होता है. कम उम्र में निवेश शुरू करके उसे लॉन्ग टर्म के लिए चालू रखने पर करोड़पति बनने का लक्ष्य पाया जा सकता है।

MUTUAL FUND INVESTMENTS ARE SUBJECT TO MARKET RISKS, READ ALL SCHEME RELATED DOCUMENTS CAREFULLY.

Timing is everything in investing, and it's Invest O'Clock now! Don't wait any longer - dive into SIP and let your money work for you.

विदेशी बाजारों में कैसे लिस्ट हो सकेगी भारतीय कंपनियां ? मोदी सरकार कर रही विचार

भारतीय शेयर बाजार में कई कंपनियां लिस्ट हैं. इन कंपनियों में कई बड़ी कंपनियां मौजूद हैं तो कई छोटी कंपनियां भी मौजूद हैं. वहीं अब विदेशी शेयर बाजार में कंपनियां कैसे लिस्ट हो, इसके लिए सरकार की ओर से काम किया जा रहा है. आइए जानते हैं इसके बारे में...

देश में केंद्र सरकार की ओर से विकास के लिए कई प्रकार के कदम उठाए जा रहे हैं. वहीं देश के आर्थिक हालात को समझने के लिए शेयर बाजार भी काफी अहम भूमिका निभाता है. इस बीच वहीं अब मोदी सरकार की ओर से देश की कंपनियों को विदेशी शेयर बाजारों तक पहुंच बनाने के लिए भी कोशिश की जा रही है. कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय घरेलू कंपनियों को सीधे विदेशी शेयर बाजारों में लिस्ट होने से संबंधित नियम बनाने के लिए पात्रता शर्तों समेत विभिन्न पहलुओं पर विचार कर रहा है. एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी.

शेयर बाजार में लिस्टिंग

फिलहाल घरेलू बाजार में लिस्टेड कंपनियां ही विदेशी बाजार में लिस्टेड हो सकती हैं. इस लिस्टिंग को अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स (एडीआर) और ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स (जीडीआर) के जरिए अंजाम दिया जाता है. अधिकारी ने कहा कि मंत्रालय कंपनियों की विदेशी लिस्टिंग से संबंधित नियमों को अंतिम रूप देने के लिए वित्त मंत्रालय के साथ अन्य संबंधित पक्षों के भी संपर्क में है.

घरेलू बाजार में लिस्डेट कंपनियां

अधिकारी के मुताबिक, विदेशी बाजारों में लिस्टिंग की मंजूरी देने के लिए कंपनियों की पात्रता शर्तों एवं अन्य पहलुओं पर चर्चा की जा रही है. इस बिंदु पर भी विचार किया जा रहा है कि क्या घरेलू बाजार में लिस्डेट कंपनियों के साथ गैर-सूचीबद्ध कंपनियों को भी विदेश में लिस्ट होने की मंजूरी दी जा सकती है.

लिस्टिंग प्रावधान में संशोधन

हालांकि विदेश में सीधी लिस्टिंग की मंजूरी देने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के विदेशी लिस्टिंग प्रावधान में संशोधन करना होगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पहले कहा था कि सरकार ने घरेलू कंपनियों को वैश्विक बाजारों से पूंजी जुटाने के लिए विदेश में लिस्ट होने की मंजूरी देने का फैसला किया है. सरकार ने मई, 2020 में कोविड महामारी से राहत के लिए पैकेज की घोषणा करते समय इस कदम की जानकारी दी थी।

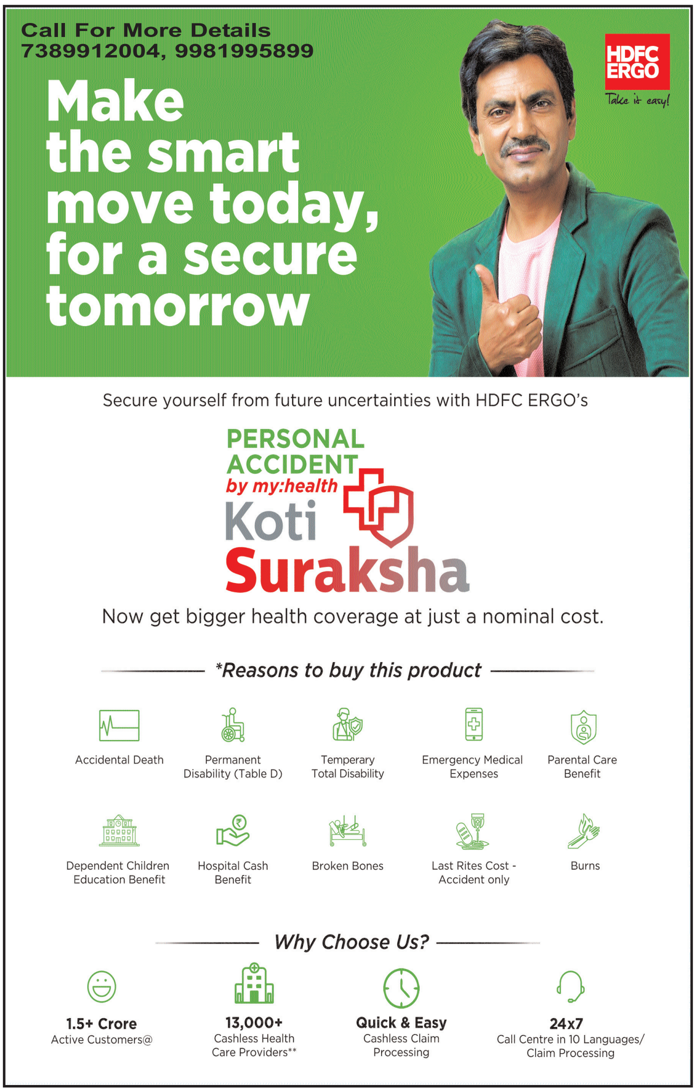

पहली तिमाही में भारत का एक्सपोर्ट घटा

चालू वित्त वर्ष में अप्रैल-सितंबर के दौरान देश का निर्यात 8.77 प्रतिशत घटकर 211.4 अरब डॉलर रहा। छह महीने की अवधि के दौरान आयात 12.23 प्रतिशत घटकर 326.98 अरब डॉलर रह गया। वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल ने कहा, भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के लिए बातचीत चल रही है और हम मतभेदों को दूर कर रहे हैं।

पेट्रोलियम व रत्न-आभूषण क्षेत्रों के लचर प्रदर्शन से देश का निर्यात सालाना आधार पर सितंबर, 2023 में 2.6 फीसदी घटकर 34.47 अरब रह गया। जिंसों की कीमतों में गिरावट से आयात भी 15 फीसदी कम होकर 53.84 अरब डॉलर रहा। आयात में यह लगातार 10वें माह गिरावट है। इससे देश का व्यापार घाटा कम होकर पांच महीने के निचले स्तर 19.37 अरब डॉलर रह गया। अगस्त, 2023 में यह बढ़कर 10 माह के उच्च स्तर 24.16 अरब डॉलर पर पहुंच गया था। सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, पिछले साल सितंबर में देश से 35.39 अरब डॉलर का निर्यात किया गया था। वहीं, 63.37 अरब डॉलर का आयात हुआ था। वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल ने कहा कि सितंबर के आंकड़े बता रहे हैं कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद निर्यात के मोर्चे पर आशा की किरण नजर आ रही है। आयात में गिरावट के कारणों पर उन्होंने कहा कि देश के आयात में कमी लाने की नीति अच्छी तरह से काम कर रही है। इसके अलावा, कच्चे तेल सहित जिंसों की वैश्विक बाजार कीमतें भी कम हो गई हैं।

रत्न-आभूषणों का निर्यात 16.03 प्रतिशत घटा

सितंबर में रत्न-आभूषणों का निर्यात 16.03 फीसदी घटकर 3.18 अरब डॉलर रह गया। पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात 10.59 फीसदी गिरकर 6.49 अरब डॉलर पर आ गया। इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों, मसाले और फल-सब्जी के निर्यात में भी गिरावट दर्ज की गईहै।

पहली छमाही में 8.77 फीसदी घटा निर्यात

चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही यानी अप्रैल-सितंबर में निर्यात 8.77 प्रतिशत घटकर 211.4 अरब डॉलर रह गया। आयात भी 12.23 फीसदी कम होकर 326.98 अरब डॉलर रहा। देश का व्यापार घाटा 115.58 अरब डॉलर रहा।

कच्चे तेल की खरीद 20.32 फीसदी घटी

पेट्रोलियम और क्रूड आयात सितंबर में 20.32 फीसदी गिरकर 13.9 अरब डॉलर रहा।खाद्य तेल का आयात 24.11 फीसदी कम होकर 1.47 अरब डॉलर रह गया।चांदी के आयात में 89.94 फीसदी कमी आईहै। उर्वरक आयात में भी गिरावट रही।

दूसरी छमाही में होगी सकारात्मक बढ़ोतरी

बर्थवाल ने कहा, भारत का निर्यात क्षेत्र अच्छा कर रहा है। कार्यालय उपकरणों के लिए तुर्किये व दवा निर्माण के लिए फिनलैंड, माल्टा व फिलीपीन जैसे नए बाजारों में भी प्रवेश कर रहा है। चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में देश के निर्यात में सकारात्मक वृद्धि की उम्मीद है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई में जो गिरावट दोहरे अंकों में था, वह अब इकाई अंकों में है।

ब्राजील के साथ ₹50 अरब डॉलर का व्यापार संभव

वाणिज्य सचिव ने कहा, भारत व ब्राजील 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को तीन गुना से अधिक बढ़ाकर 50 अरब डॉलर करने के लक्ष्य पर विचार कर रहे हैं। बर्थवाल ने कहा, वर्तमान में इस्राइल-हमास संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति पर ज्यादा असर नहीं दिख रहा है।मौजूदा तनाव पर हम करीब से नजर रखे हुए हैं।

देश में महिला श्रम बल की भागीदारी 4.2 प्रतिशत बढ़कर 37 प्रतिशत हुई

सरकार ने शुक्रवार को कहा कि देश में महिला श्रम बल की भागीदारी दर 2023 में 4.2 प्रतिशत बढ़कर 37 प्रतिशत हो गई है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, महिला श्रम बल भागीदारी दर 2017-18 में 23.3 प्रतिशत से बढ़कर 2018-19 में 24.5 प्रतिशत हो गई; 2019-20 में 30 प्रतिशत से 2020-21 में 32.5 प्रतिशत और 2021-22 में 32.8 प्रतिशत से 2022-23 में 37 प्रतिशत हो गया। मंत्रालय ने कहा, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा नौ अक्टूबर, 2022 को जारी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 से पता चलता है कि श्रम बल भागीदारी को मापने की सामान्य स्थिति की अवधारणा के अनुसार देश में महिला श्रम बल भागीदारी दर 2023 में 4.2 प्रतिशत अंक बढ़कर 37 प्रतिशत हो गई है।

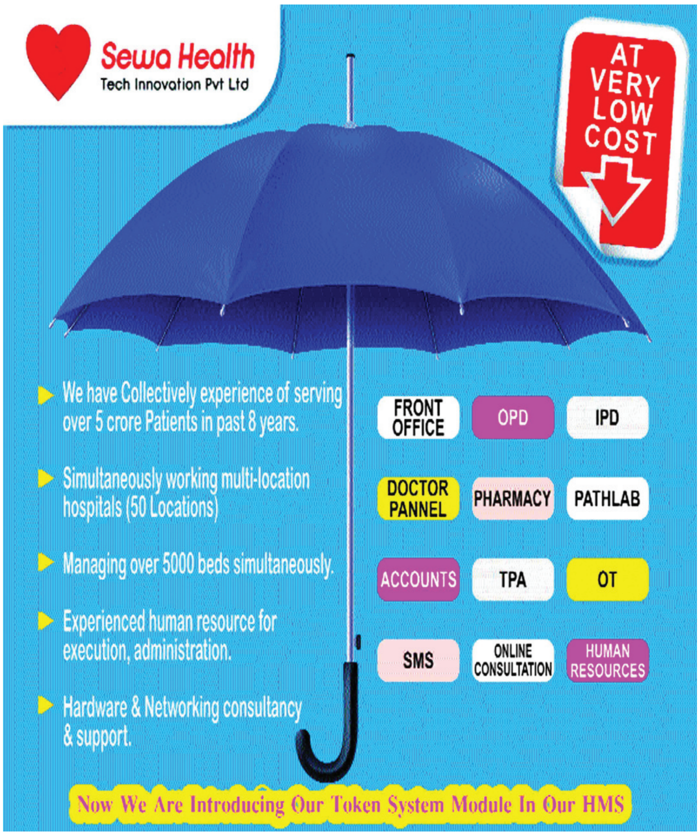

संपादकीय

■ अवनीश तिवारी | सहायक संपादक

डिजिटल भुगतान पर बढ़ता जा रहा है भारतीयों का भरोसा

भारत में जब डिजिटल भुगतान शुरू हुआ था तो किसी को यह नहीं पता था कि यह डिजिटल भुगतान इतनी शीघ्रता से बढ़ता जाएगा और इस पर देशवासी इतना अधिक विश्वास जताएंगे। उल्लेखनीय है कि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) के आंकड़ों के अनुसार 30 अगस्त को यूपीआइ लेनदेन का आंकड़ा 10.24 अरब हो गया। इन लेनदेन का मूल्य 1518456.4 करोड़ रुपये रहा। जुलाई में यूपीआइ लेनदेन की संख्या 9.96 अरब थी जबकि जून में यह 9.33 अरब थी। अगस्त 2021 में यूपीआई के माध्यम से लेनदेन का आंकड़ा केवल 3.5 बिलियन था जो दो वर्षों में लगभग तीन गुना बढ़ चुका है। एकीकृत भुगतान व्यवस्था (UPI) के जरिये लेनदेन का आंकड़ा अगस्त में 10 अरब को पार कर गया। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) के आंकड़ों के अनुसार, 30 अगस्त को यूपीआइ लेनदेन का आंकड़ा 10.24 अरब हो गया। इन लेनदेन का मूल्य 15,18,456.4 करोड़ रुपये रहा। जुलाई में यूपीआइ लेनदेन की संख्या 9.96 अरब थी जबकि जून में यह 9.33 अरब थी। एनपीसीआइ देश में सभी खुदरा भुगतान प्रणालियों का मुख्य संगठन है।

अगस्त 2021 में यूपीआई के माध्यम से लेनदेन का आंकड़ा केवल 3.5 बिलियन था, जो दो वर्षों में लगभग तीन गुना बढ़ चुका है। हमारे देश में अब अधिकांश व्यापारी यूपीआई के जिए लेनदेन पर भरोसा दिखा रहे हैं। आज के समय करोड़ों की कमाई करने वाले व्यापारी हो या सब्जी बेचने वाले छोटे-मंझोले दुकानदार, सभी यूपीआई के जरिए लेनदेन कर रहे हैं।

उल्लेखनीय है कि 35 से अधिक देश अब भारत की यूपीआई तकनीक को अपनाना चाहते हैं। जापान उन देशों में शामिल है जिन्होंने हाल ही में यूपीआई को अपनाने में रुचि व्यक्त की है।

साल 2016-17 मे नोटबंदी के दौरान भारत सरकार ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा दिया। साल 2016 में मोदी सरकार ने PI-BHIM लॉन्च किया था। नोटबंदी के बाद बड़े पैमाने पर लोगों ने डिजिटल भुगतान पर भरोसा किया। इसके बाद कोविड महामारी के दौरान डिजिटल भुगतान के जरिए देश के ज्यादातर लोग पैंसों के भुगतान के लिए कैश की जगह यूपीआई को चुना और आज के समय हर तरफ कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक यूपीआई पर भारतीयों का अटूट भरोसा है। यह लगातार बढ़ता जा रहा है। आनेवाले समय में इसके और अधिक बढ़ने की संभावना है। उल्लेखनीय है देश हर वर्ग अब इसे उपयोग करने लगा है।

चीन का आर्थिक विकास धीमा हुआ भारत का प्रदर्शन कहीं बेहतर : IMF

भोपाल। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, यानी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड (IMF) ने अगले दो वर्ष के लिए चीन के आर्थिक विकास के अपने पूर्वानुमान को घटा दिया है, और बताया है कि चीन में रियल एस्टेट क्षेत्र में मौजूद दिक्कतों के चलते हुआ कम निवेश इसके पीछे की प्रमुख वजह है। दूसरी ओर, IMF का मानना है कि चीन का पड़ोसी देश भारत उसकी तुलना में बेहतर प्रदर्शन करेगा, और वर्ष 2024 के लिए आउटलुक में बदलाव किए बिना इस वर्ष के लिए भारत के आर्थिक विकास पूर्वानुमान को बढ़ाकर 6.3 प्रतिशत कर दिया है।

IMF की मंगलवार को जारी द्विवार्षिक वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार, चीन को लेकर IMF का अनुमान है कि इस वर्ष चीन का आर्थिक विकास 5 प्रतिशत और 2024 में 4.2 प्रतिशत की दर से होगा, जो पहले के अनुमान की तुलना में क्रमश: 0.2 प्रतिशत तथा 0.3 प्रतिशत कम है।

चीन को लेकर IMF का अनुमान है कि इस वर्ष चीन का आर्थिक विकास 5 प्रतिशत और 2024 में 4.2 प्रतिशतकी दर से होगा, जो पहले के अनुमान की तुलना में क्रमशः 0.2 प्रतिशत तथा 0.3 प्रतिशत कम है।

IMF के चीफ इकोनॉमिस्ट पियरे-ओलिवियर गौरिन्चास ने कहा, चीन में इस सेक्टर में वास्तव में भरोसा लौटाने के लिए सरकार की तरफ से बेहद शक्तिशाली और बेहद बड़ी कार्रवाई की ज़रूरत होगी, ताकि ट्रेंड से कम विकास के अनुमान को बदला जा सके...। मिडिल ईस्ट और मध्य एशिया के लिए इस वर्ष के विकास परिदृश्य को आधा प्रतिशत घटाकर 2.0 प्रतिशतकर दिया गया है, जो दरअसल तेल-समृद्ध सऊदी अरब के विकास पूर्वानुमान में आई गिरावट के चलते घटा है।

इसके अलावा, सब-सहारा अफ्रीका में आउटलुक कुछ बिगड़ गया है, और अनुमानित मंदी के बीच नाइजीरियाई अर्थव्यवस्था में विकास दर 3.3 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जो पिछले अनुमानों से 0.2 प्रतिशत कम है।

WEEKLY STOCK PIVOT LEVEL

Anil Bhardwaj
Technical Head
anilstockcare@gmail.com

All level indicated above are based on future prices PP: Pivot Point: This is Trigger Point for buy/sell Based on the price range of the previous Month R1: Resistance one: 1st Resistance over PP. R2: resistance Two: 2nd Resistance over R1.S1: Support one: 1st support after PP. S2: Support Two: 2nd support after S1. 1)

- As per tool, trader should take Buy position just above pp and keep the stop loss of PP and teh first target would be R1.2)
- If R1 is crossed then R2 becomes the next target with the stop loss at R1. 3)
- If R2 is crossed then R3 becomes the next target with the stop loss at R2.
- Similarly if price goes below PP the trader should SELL and keep the PP as stop loss and the first target would be S1.
- If S1 is crossed then S2 becomes the next target with the stop loss at S1.
- If S2 is crossed then S3 becomes the next target with the stop loss at S2.

	Stock name	R3	R2	R1	PP	S1	S2	S3
2	NIFTY	20251	20046	19890	19685	19529	19324	19168
3	BANK NIFTY	45491	45148	44682	44239	43773	43330	42864
4	ACC	2161	2109	2060	2008	1959	1907	1858
5	ALKYAMINES	2364	2341	2302	2279	2240	2217	2178
6	AXISBANK	1062	1046	1020	1004	978	962	936
7	BHARTIARTL	1008	982	968	942	927	902	887
8	CIPLA	1220	1203	1185	1168	1150	1133	1115
9	DLF	625	601	585	561	545	521	505
10	ESCORTS	3767	3599	3489	3321	3211	3043	2933
11	GSPL	303	299	292	288	281	277	270
12	GRINFRAPOJECT	1263	1246	1223	1206	1183	1166	1143
13	HDFCBANK	1590	1571	1552	1532	1513	1493	1474
14	HCLTECH	1341	1307	1282	1248	1223	1189	1164
15	HINDALCO	522	508	494	479	464	450	435
16	HINDUNILVR	2697	2637	2601	2541	2505	2445	2409
17	IRCT	731	721	713	704	695	685	677
18	ICICIBANK	988	975	962	949	936	923	910
19	IEX	144	140	137	134	130	127	123
20	INFY	1594	1556	1494	1456	1394	1356	1294
21	ITC	471	462	455	446	439	430	423
22	KOTAKBNK	1846	1813	1784	1750	1720	1687	1657
23	LT	3167	3138	3114	3085	3061	3032	3008
24	LUPIN	1260	1226	1208	1174	1156	1122	1104
25	MARUTI	11482	1112	10925	10555	10368	9998	9811
26	M&M	1646	1610	1586	1550	1526	1490	1466
27	MGL	1198	1171	1149	1122	1100	1073	1051
28	NCC	182	174	168	160	154	146	140
29	RELIANCE	2435	2397	2371	2333	2307	2269	2243
30	RECLTD	318	308	300	289	282	272	264
31	SBIN	612	604	590	582	568	560	546
32	SBICARD	840	823	806	790	773	757	740
33	SUNPHARMA	1192	1169	1155	1132	1118	1095	1081
34	TITAN	3366	3336	3310	3280	3254	3224	3198
35	TCS	3809	3744	3659	3594	3509	3444	3359
36	TATASTEEL	131	129	127	125	123	121	119
37	TATAMOTORS	741	705	686	650	631	595	576
38	UPL	666	648	635	617	604	586	573
39	WIPRO	442	433	422	413	402	393	382

New RBI rule to make debit card, credit card online transactions faster, secure: Tokenisation at banks explained

Using your debit cards and credit cards online will become more secure and easy as the Reserve Bank of India (RBI) has allowed banks to generate tokens for your cards. At present, you can create tokens only through e-commerce websites while making online payments through your cards. What is the new card tokenisation rule and how is it going to help you? Read on to find out.

What is card tokenisation?

Let's understand what tokenisation is, first. Card tokenisation is a major reform to enhance the security of online transactions. Tokenisation refers to the replacement of actual card details with an alternate code called the "token", which will be unique for a combination of cards, the token requestor (i.e., the entity which accepts a request from the customer for tokenisation of a card, and passes it on to the card network to issue a corresponding token) and device (referred hereafter as "identified device"), as per the FAQs released by the Reserve Bank of India (RBI).

Earlier, RBI directed payment aggregators, wallets, and online merchants (entities in card transaction/ payment chains other than card issuers/card networks) not to store any sensitive card-related customer information including full card details. Hence, the card numbers can be replaced with 'tokens' as mentioned above. This mandate came into effect from October 1, 2022.

Card-on-File tokenisation at issuer bank: What is new?

As of now, tokens could can only be created at various merchant websites. When you are making a transaction on a merchant website for the first time, you get an option to 'secure your card as per RBI guidelines' at the time of checkout. When you opt for this, a secure token is generated, and the same is stored in the merchant's database instead of your actual card details. Now, the regulator has proposed to introduce Card-on-File token creation facilities directly at the issuer bank level.

Sharing a glimpse of how the Card-on-File tokenisation will work at the bank levelr, Rahul Jain – CFO, of NTT DATA Payment Services India, says "So, while making online payments through debit card and credit card, the 'token request' will now be sent to the issuer bank who will then validate it for authenticity and security purposes. Once the token request is approved, the issuer bank will create a unique token linked to the card details shared by the users. To initiate the transaction, the merchant uses the token to request payment authorisation from the issuer bank. Upon receiving a tokeniszed payment request, the issuer bank uses the token to refer to the user's card details stored in their database. The bank then initiates the transaction as they would with the original card information."

How debit card, credit card tokenisation at issuer banks makes your online transaction secure and faster

A tokenised card transaction is considered safer as the actual card details are not shared or stored with the merchants to perform the transaction. Instead, tokens of your card details are used for all the online payments you make to the merchants. The central bank introduced tokens to reduce fraudulent activities and safeguard card data, consequently enhancing the convenience and safety of transactions for customers. "Till now, the cardholders had to create different tokens through each merchant's application or webpage. This would require time and effort from the users. Going forward, tokens will be created at the issuer bank-level and linked to their existing accounts with various e-commerce applications," says Mandar Agashe, Founder & Managing Director at Sarvatra Technologies.

Moreover, this move will eliminate the duplication of tokenisation process at each app or website along with increased transaction security, resulting in reduced card-data-related frauds, says Agashe.

Simply put, you don't even have to use your 16-digit debit or credit card number while making an online transaction. You can just use a token issued by your bank. So, your debit or credit card numbers are not required to be exposed to a new online merchant anymore. "This move bolsters security through unique tokens and provides a streamlined, user-friendly experience. CoF tokeniszation, acting as a digital guardian for your sensitive card information, represents a smart and convenient change set to make transactions simpler," says Gaurav Jalan, CEO and founder, mPokket.

Do note that e-commerce platforms or payment aggregators or online merchants are not allowed to save your debit or credit card details now. So, if you do not wish to create a token, you have to enter the card numbers, expiry date, and CVV every time you make a transaction on that website.

As you can now create card tokens at your bank, you will be able to easily add or delete tokens on the bank website or application. So, you don't have to go through the hassle of creating and deleting tokens on some platforms that you have used at one point but do not use anymore. You can just use the token issued by your bank for all your online transactions through debit and credit cards. Explaining this further, Adhil Shetty, CEO, of BankBazaar.com, says, "The expectation is that once this is implemented, you would be able to create and manage your card tokens for the e-commerce sites directly from your bank account, pretty much like setting your credit limits and spending limits over net banking or banking app. This gives you greater control over managing your card token and allows you to add, modify, and delete tokens remotely, without accessing the website."

This process poses minimal challenges for issuer banks, as most of them can leverage the existing unified payment system framework for token creation, says Jain. "This strategic move not only promotes safer and more secure card transactions but also enhances overall transaction efficiency."

What are the benefits of Card on File tokenisation at the issuer banks?

Identifying three core benefits of card tokenisation, Jain says

1) **Tokenisation streamlines the checkout process, eliminating the need for customers to repeatedly input their card information for each purchase.**

2) **Tokenisation enhances the overall customer experience, simplifying and expediting the payment process for customers.**

3) **Tokenisation aims to reduce fraudulent activities and safeguard card data.**

curtsey: https://economictimes.indiatimes.com/

एक वर्ष या छोटी अवधि के लिए निवेश करना है पैसा तो हाई रिटर्न देने वाले ये 4 ऑप्शंस आएंगे काम

भोपाल। सभी लोगों का मानना है, कि निवेश लंबे समय के लिए करो, ताकि लाभ भी बड़ा हो। लेकिन कई बार ऐसी स्थिति सामने आ जाती है, जब आपको अचानक से पैसों की आवश्यकता होती है। ऐसे में आपको पैसों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अपनी एफडी या दूसरी पॉलिसीज को मैच्योरिटी से पहले ही तुड़वाना पड़ जाता है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए आवश्यक है कि आप अपने पैसे को लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करने के साथ-साथ छोटी अवधि वाली स्कीम्स में भी निवेश करें। ताकि कठिन समय छोटी अवधि वाली स्कीम्स का पैसा आपके काम आ सके। यहां जानिए उन ऑप्शंस के बारे में जहां आप एक वर्ष के लिए भी निवेश कर सकते हैं और अच्छा रिटर्न भी प्राप्त कर सकते हैं।

बैंक एफडी

निवेश के तमाम ऑप्शंस होने के बाद भी एफडी को बहुत रूचिकर विकल्प माना जाता है। आप किसी भी बैंक में 7 दिन से लेकर 10 वर्ष तक की एफडी करवा सकते हैं। अलग-अलग टाइम पीरियड के हिसाब से ब्याज दर भी अलग-अलग होती है। पोस्ट ऑफिस में भी आपको 1 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक की एफडी का विकल्प मिलता है, आप उसे भी चुन सकते हैं। एफडी कराने से पहले बैंकों और पोस्ट ऑफिस की ब्याज दरों को कंपेयर करें, उसके बाद एक वर्ष की एफडी करवाएं।

कॉर्पोरेट एफडी

कई कंपनियां अपने कारोबार के लिए मार्केट से पैसा जुटाती हैं और इसके लिए वो कंपनी एफडी जारी करती हैं। यह बिल्कुल उसी तरह से काम करती है, जैसे बैंक एफडी। इसके लिए फॉर्म कंपनी जारी करती है, जिसे ऑनलाइन भी भर सकते हैं। कॉरपोरेट एफडी में ब्याज दर बैंक एफडी की तुलना में ज्यादा होती है। हालांकि बैंक एफडी की तुलना में कॉर्पोरेट एफडी के मामले में जोखिम थोड़ा ज्यादा होता है। लेकिन मजबूत और ज्यादा रेटिंग वाली कंपनियों की एफडी में जोखिम कम होता है। आमतौर पर कॉरपोरेट एफडी का मेच्योरिटी पीरियड 1 से 5 वर्ष तक होता है। आप अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी अवधि चुन सकते हैं।

रेकरिंग डिपॉजिट

रेकरिंग डिपॉजिट को सामान्य भाषा में आरडी के तौर पर जाना जाता है। ये स्कीम एक तरह की गुल्लक की तरह है, जिसमें हर महीने आपको एक निश्चित अमाउंट जमा करना होता है। मैच्योरिटी पर आपको कुल रकम ब्याज समेत मिलती है। आरडी में भी आप एक वर्ष से लेकर अलग-अलग अवधि का विकल्प चुन सकते हैं। सभी बैंकों में आपको आरडी की सुविधा मिल जाएगी। आप तमाम बैंकों में आरडी पर मिलने वाली ब्याज दर की तुलना करें और जहां भी ज्यादा ब्याज मिले वहां पैसा इन्वेस्ट करें। आरडी का ऑप्शन आपको पोस्ट ऑफिस में भी मिलता है, लेकिन वहां इसकी अवधि 5 वर्ष की होती है।

डेट म्यूचुअल फंड

एक वर्ष के लिए निवेश करना है तो आप डेट म्यूचुअल फंड का विकल्प भी चुन सकते हैं और 12 महीनों के लिए पैसा इसमें निवेश कर सकते हैं। आप डेट फंड में जो भी निवेश करते हैं, उसे सुरक्षित जगह पर निवेश किया जाता है। आमतौर पर डेट फंड की तय मैच्योरिटी डेट होती है। इसमें भी आपको काफी अच्छा रिटर्न मिल सकता है।

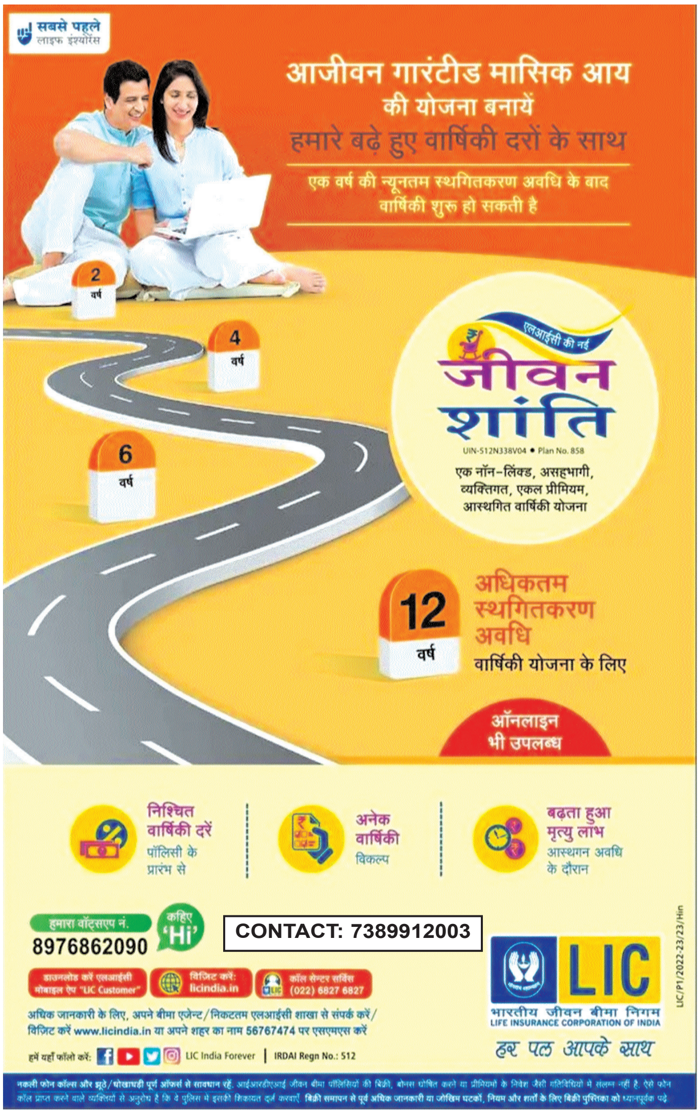

प्रकाशक एवं मुद्रक : प्रदीप करम्बेलकर, सी-101, नेहरू नगर द्वारा स्वात्वाधिकार विजन एडवायजरी सर्विसेस प्रा.लि. प्लॉट नं.-36, ई-सेकण्ड फ्लोर, जोन-2, एम.पी. नगर, भोपाल (म.प्र.) से प्रकाशित एवं महक ग्राफिक्स एण्ड ऑफसेट, प्लॉट नं.-4, वैभव काम्प्लेक्स, जोन-1, एम.पी. नगर, भोपाल (म.प्र.) से मुद्रित। सम्पादक प्रदीप करम्बेलकर (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल रहेगा) फोन : 91-0755-2555186, 2555217 वेबसाइट : 222.investmentavenues.in ईमेल : contactinvestmentavenues@gmail.com